



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, सामवार, सितम्बर 11, 2017/भाद्र 20, 1939

No. 240]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 2017/ BHADRA 20, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

सं. यू-23013/01/2017-एलडब्ल्यू.—ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ठेका श्रम सलाहकार यवतमाल, महाराष्ट्र में भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम प्रणाली के उत्सादन की जांच करने के लिए एतद्वारा एक समिति का गठन करता है।

2. समिति का गठन इस प्रकार होगा:—

- |      |   |               |
|------|---|---------------|
| i.   | डॉ. विवेक मोनटेरियो<br>सचिव,<br>कार्यालय मुंबई श्रमिक संघ, क्वेरी रोड,<br>भांडुप, मुंबई- 400078                             | —सदस्य        |
| ii.  | कार्यकारी निदेशक<br>कार्मिक एवं प्रशासनिक,<br>स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,<br>इस्पात भवन, लोदी रोड,<br>नई दिल्ली-110003 | —सदस्य        |
| iii. | क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (कें.)<br>प्रथम तल, ब्लॉक -सी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स<br>सेमीनरी हिल्स, नागपुर- 440006                     | —सदस्य संयोजक |

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषयनिम्नानुसार होंगे—

“भारत संचार निगम लिमिटेड यवतमाल, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में इलैक्ट्रिक रखरखाव, इलैक्ट्रिक प्रचालक, ए/सी रखरखाव, जेनरेटर प्रचालक, रोजमर्रा के कामों के विनियम के रखरखाव और देखभाल, भूमिगत केबल रखरखाव, केबल जोड़ने वाले, लाइन रखरखाव, डेटा इंटी प्रचालक ब्राड बैंड रखरखाव, लाईन खराबी, सफाई और झाड़पोंछ,

सुरक्षा दरबान, टॉवर रखरखाव, लाइनमैन, सहायक की नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रमिक प्रणाली के कार्यसंचालन का अध्ययन करना तथा उपयुक्त सिफारिशें करना कि ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान की उपर्युक्त नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रमिकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं।”

4. समिति का मुख्यालय नागपुर में होगा। समिति पक्षकारों को नए सिरे से सुनेगी, पक्ष रखने की अनुमति देगी तथा अपनी रिपोर्ट दो महीने के अंदर प्रस्तुत करेगी।

[फा. सं. यू-23013/01/2017-एल.डब्ल्यू.]

ए. के. सिंह, सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**  
(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

**RESOLUTION**

New Delhi, the 11th September, 2017

**No. U-23013/01/2017-LW.**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour system in the establishment of Bharat Sanchar Nigam Limited at Yavatmal, Maharashtra.

2. The composition of the Committee will be as under:—

- |      |   |                  |
|------|---|------------------|
| i.   | Dr. Vivek Monterio<br>Secretary,<br>Office of Mumbai Shramik Sangh, Quarry Road,<br>Bhandup, Mumbai-400078  | —Member          |
| ii.  | The Executive Director,<br>Personnel and Administrative,<br>Steel Authority of India Limited,<br>Ispat Bhawan, Lodhi Road,<br>New Delhi – 110003. | —Member          |
| iii. | The Regional Labour Commissioner(C),<br>1 <sup>st</sup> Floor, Block-C, CGO Complex,<br>Seminary Hills, Nagpur – 440006.                          | —Member Convenor |

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:—

“To study the working of contract labour system in the jobs/works of Electric Maintenance, Electrical Operator, A/C Maintenance, Generator Operator, Maintenance & Up-keepment of the Exchange day to day work, Underground Cable Maintenance, Cable Jointer, Line Maintenance, Data Entry Operator, Broadband Maintenance Line Fault, Cleaning & Dusting, Security Guard, Tower Maintenance, Lineman, Helper in the establishment of Bharat Sanchar Nigam Limited at Yavatmal, Maharashtra and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.”

4. The Headquarter of the Committee will be at Nagpur. The Committee shall hear the parties afresh, allow submission and submit its report within two months.

[F. No. U-23013/01/2017-LW]

A. K. SINGH, Secy.